

Need to increase the Minimum Support Price of sugar

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, भारतीय चीनी उद्योग का एक लंबा और संपन्न इतिहास रहा है। गन्ने से चीनी बनाना प्राचीन काल से चला रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। देश का चीनी उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह चीनी उद्योग देश के करीब 10 करोड़ से ज्यादा गन्ना उत्पादक किसानों के परिवार का जीविका का साधन है। देश में करीब 550 चीनी मिलें हैं। इस उद्योग से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमारे देश में हर साल करीब 360 से 400 लाख मीट्रिक टन तक शुगर का उत्पादन होता है। 2022-23 में हमने करीब 60 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट भी किया था। हमारा जो डोमेस्टिक शुगर कंजंप्शन है, वह करीब 260 लाख टन है। गन्ना उत्पादक जो फसल उत्पन्न करते हैं, उसकी gross value करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन यह पूरा उद्योग climate change पर निर्भर करता है। कभी कम, तो कभी ज्यादा बारिश से इस उद्योग को भारी नुकसान भी होता है। केंद्र की सरकार ने शुगरकेन का price, यानी FRP, Fair and Remunerative Price निश्चित किया है, जो recovery पर आधारित है। हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होता है। यह एफआरपी किसानों को 2,800 से 3,300 रुपये प्रति टन तक की इनकम दिलाता है। इसी तरह गवर्नमेंट ने चीनी का भी एमएसपी निश्चित किया है, जो 3,100 रुपये है। पिछले 7 सालों से एमएसपी का रेट 3,100 रुपये है। एक तरफ एफआरपी हर साल बढ़ रहा है, लेकिन चीनी का जो एमएसपी है, वह 3,100 रुपये पर ही सीमित है। इसकी वजह से चीनी मिलों को भारी नुकसान हो रहा है। चीनी मिलों में गन्ना crushing करने के बाद जो चीनी निकलती है, उसकी जो production cost है, harvesting, transportation, maintenance, salaries and interest — यह 42 रुपये से 45 रुपये तक बढ़ गयी है। आप समझ सकते हैं कि production cost 42 रुपये है और शुगर का selling price 31 रुपये ही रहने से यह काम संभव नहीं हो रहा है। देश की सभी संस्थाओं ने, ISMA, National Sugar Federation, महाराष्ट्र साखर संघ ने सरकार से यह मांग की है कि चीनी का सेलिंग प्राइस, एमएसपी 42 रुपये किया जाए, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को ज्यादा लाभ होगा और समय पर उनकी फसल का भुगतान भी हो पाएगा तथा जो चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं या जो चीनी मिलें बंद होने की कगार पर हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। उपसभापति जी, हमारे देश में जो चीनी निर्मित होती है, उसमें से 75 परसेंट चीनी इन प्रोडक्ट्स के लिए यूज की जाती है — जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मिठाई आदि, जो आम इंसान की खास जरूरतों, जैसे जीवन आवश्यक वस्तुओं में नहीं गिनी जातीं।

...(समय की घंटी)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik: Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Govindbhai Laljibhai Dholakia (Gujarat), Dr. Sasmit Patra

(Odisha), Shri Ravi Chandra Vaddiraju (Telangana), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu) and Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim)
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Neeraj Dangi- Request to use Artificial Intelligence for monitoring the endangered wildlife species.

Request to use Artificial Intelligence for monitoring the endangered wildlife species

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : महोदय, आज देश के सामने वन्य जीवों को लेकर एक बड़ी चुनौती है और विशेष रूप से जो लुप्तप्राय हो रही प्रजातियाँ हैं, जिनमें टाइगर, लेपर्ड, चीता आदि बड़ी बिल्लियों की श्रेणियाँ शामिल हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए यह एक चुनौती है।

महोदय, देश में लुप्तप्राय वन्य जीवों, टाइगर, लेपर्ड आदि के संरक्षण हेतु उनकी निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की जानी चाहिए। उसके आकार, उसकी चाल आदि से यह पता लगाया जा सकता है कि वह कौन सा जानवर है, जंगल में क्या गतिविधि कर रहा है और कहाँ पर गतिविधि कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पहचान प्रणालियाँ अधिक लागत प्रभावी भी हैं और जो पारंपरिक तरीके हैं, उनकी तुलना में इसमें कम कार्य बल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण हमारे पर्यावरण के कल्याण और भविष्य के मानव कल्याण में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अगर इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किया जाए, तो देश के लिए इनका बहुत ही बेहतरीन संरक्षण होगा। हमें इंसानों को भी बचाना है और वन्य जीवों को भी बचाना है। वन्य जीव जब जंगल के आसपास के गांवों में घुस जाते हैं, तब वे मनुष्यों और उनके मवेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उस वजह से मनुष्यों का वन्य जीवों के प्रति एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई पुख्ता

(श्री सभापति पीठासीन हुए।)

व्यवस्था की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वन्य जीवों को और मनुष्यों को, दोनों को बचाने का कार्य इस प्रणाली से किया जा सकता है। अभी हाल ही में रणथम्भौर के अन्दर देखा गया कि 25 बाघों के लापता होने की खबर आई। ...**(समय की घंटी)**...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Neeraj Dangi: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sandosh Kumar P (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh) and Shri Saket Gokhale (West Bengal).